उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 | अंक 20 | 16-31 अक्टूबर 2021 | ₹ 20/-

बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे

- मोदी की रैली में बम धमाके करने वालों को फांसी
- शिया मुसलमानों को निशाना बनाने की धमकी
- सूडान में सैनिक विद्रोह
- चीन की कुरान दुश्मनी

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

मोदी की रैली में बम धमाके करने वालों को फांसी 04
हज के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू 06
पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई 07
जिन्ना पर अखिलेश यादव के बयान से हंगामा 10
त्रिपुरा के घटनाक्रम की आड़ में मुस्लिम संगठन सक्रिय 11
गुरुग्राम में नमाज पढ़ने पर विवाद 13

विश्व

बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे 14
इस्लामिक स्टेट की शिया मुसलमानों को निशाना बनाने की धमकी 17
ब्रिटिश सांसद की जिहादी द्वारा हत्या 18
रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप पर हमला 18
चीन द्वारा अफगानिस्तान में पूंजी निवेश की तैयारी 19

पश्चिम एशिया

सूडान में सैनिक विद्रोह 20
नाइजीरिया में मस्जिद पर हमले में 18 मरे 21
मिस्र में आपातकाल समाप्त 22
तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का कड़ा कदम 23
अरब इत्तेहाद का यमन में फौजी ऑपरेशन 24

अन्य

चीन की कुरान दुश्मनी 25
मौलाना महमूद मदनी प्रभावी नेताओं की सूची में 25
केला खाने पर सीरिया के शरणार्थी तुर्की से निष्कासित 25
मौलाना हकीम अब्दुल्ला को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 26
मौलाना अरशद मदनी विवादों के घेरे में 26

सारांश

2013 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी की पटना में आयोजित 'हुंकार रैली' में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने खून की होली खेली थी। पटना में हुए धमाकों में कम-से-कम छह निर्दोष मारे गए थे और लगभग 80 व्यक्ति घायल हो गए थे। कहा जाता है कि इन धमाकों के तार पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए थे। पटना के एक न्यायालय ने इस सीरियल बम धमाके से जुड़े हुए नौ लोगों को सजा सुनाई है। इनमें से चार को फांसी की सजा दी गई है।

उर्दू समाचारपत्र अपने पाठकों को उत्तेजित करने के लिए राई का पहाड़ बना रहे हैं। सभी उर्दू समाचारपत्र त्रिपुरा की घटना को उछालकर मुस्लिम मतदाताओं को भड़काने के प्रयास में जुटे हुए हैं। हालांकि इन्हीं समाचारपत्रों ने बांग्लादेश में हुए हिंदू विरोधी दंगों को लगभग नजरअंदाज कर दिया है। बांग्लादेश में हुए इन दंगों में दो दर्जन से अधिक लोग मारे गए हैं और 200 से अधिक मंदिरों और हिंदू बस्तियों को अतिवादी जिहादियों ने ध्वस्त कर दिया है।

मुसलमानों के दो फिरकों शिया और सुन्नियों के झगड़े गंभीर रूप ले रहे हैं। हाल ही में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने यह घोषणा की है कि वे दुनिया से शियाओं का नामोनिशान मिटाकर दम लेंगे। अफगानिस्तान में जिस तरह से इस सुन्नी संगठन के आतंकवादियों की ओर से शियाओं के खून की होली खेली जा रही है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका बुरा प्रभाव अनेक देशों पर पड़ने की संभावना है जहां की आबादी में शिया और सुन्नी दोनों शामिल हैं।

मुस्लिम नेता अरशद मदनी इन दिनों अतिवादियों के निशाने पर इसलिए आ गए हैं क्योंकि उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने के अतिरिक्त टीवी चैनल सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चव्हाणके को एक इंटरव्यू दिया है। उनकी इन गतिविधियों को कट्टरवादी मुसलमानां ने पसंद नहीं किया है और उनकी खुलेआम आलोचना शुरू कर दी है।

यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग भारतीय होने का लाभ उठाते हैं वे क्रिकेट मैंच में पाकिस्तान के हाथों भारत के हार जाने पर खुलेआम जश्न मनाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। हाल ही में दुबई में हुए टी-20 वर्ल्ड कप मैच में भारत की हार पर इन पाकिस्तान परस्त तत्वों ने जमकर जश्न मनाया। दु:ख की बात यह है कि इस तरह का जश्न देश के कई भागों में मनाया गया और उनमें प्रबुद्ध छात्र सबसे आगे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि इन देशद्रोही गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर आदि अनेक राज्यों में ऐसे तत्वों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं।

गत कई दशकों से इस्लामिक देश सूडान में जो राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी उसने हाल ही में एक नया मोड़ लिया है। वहां की सेना ने विद्रोह करके पुरानी सरकार के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को बंदी बनाने के बाद सत्ता की बागडोर स्वयं संभाल ली है।

मोदी की रैली में बम धमाके करने वालों को फांसी

मुंबई उर्दू न्यूज (2 नवंबर) के अनुसार बिहार की राजधानी पटना में 2013 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान ऐतिहासिक गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर हुए बम धमाकों के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के विशेष न्यायालय ने चार आरोपियों को फांसी, दो को उम्र कैद, दो को दस-दस वर्ष कैद और एक आरोपी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों को आज भारी सुरक्षा के बीच पटना की जेल से विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा क न्यायालय में लाया गया। न्यायालयी कार्रवाई शुरू होते ही न्यायाधीश ने सजा के बारे में दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क सुने। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के विशेष वकील ललन प्रसाद सिन्हा ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की अपील की। जबकि आरोपियों के वकील सैयद इमरान गनी ने आरोपियों के आर्थिक और सामाजिक हालात का हवाला देते हुए नरमी बरतने और कम सजा देने का अनुरोध किया। शाम को न्यायालय की कार्रवाई पुनः शुरू होने के बाद आरोपियों को कैद की सजा सुनाई गई। इससे पूर्व न्यायालय ने आरोपी फखरूद्दीन को तमाम आरोपों से बरी कर दिया था। सात वर्ष की सजा पाने वाले आरोपी को अगले कुछ दिनों के भीतर जेल से रिहा किए जाने की संभावना है क्योंकि वह सात वर्ष से अधिक की अवधि जेल में पहले ही गुजार चुका है। जबकि दस वर्ष की सजा पाने वाले दोनों आरोपियों को जेल में और दो वर्ष गुजारने होंगे। 27 अक्टूबर को न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था।

अवधनामा (2 नवंबर) के अनुसार न्यायालय ने हैदर अली, मुजीबुल्लाह अंसारी, नुमान अंसारी और इम्तियाज अंसारी को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि उमर सिद्दीकी और अजहरूद्दीन कुरैशी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अहमद हुसैन और मोहम्मद फिरोज आलम को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई गई है और इफ्तिखार अहमद को सात वर्ष की सजा सुनाई गई है। जमीयत उलेमा कानूनी सहायता समिति के

संयोजक गुलजार आजमी ने पत्रकारों को बताया कि न्यायालय के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी और उन्हें बचाने के लिए देश के सर्वोच्च वकीलों की व्यवस्था जमीयत उलेमा करेगी। उन्होने आरोप लगाया कि न्यायालय ने आरोपियों के वकीलों के तर्क को नजरअंदाज किया है और इस्तगासा की ओर से पेश किए गए कमजोर सबूतों और साक्ष्यों को अहमियत दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायालय ने जांच एजेंसी की तरफ से की जाने वाली धांधलियों को नजरअंदाज किया है। इनमें आरोपियों से जबरन लिया गया इकबालिया बयान और गवाहों को धमकाकर उनसे आरोपियों के खिलाफ दिए गए बयान तथा फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट के साथ साथ गवाहों के बयान की विसंगितयों आदि महत्त्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज किया है।

27 अक्टूबर 2013 को पटना क ऐतिहासिक गांधी मैदान में कई बम धमाके तब हुए थे जब प्रधानमंत्रो नरेन्द्र मोदी एक सभा को संबांधित करने वाले थे। इन धमाकों में छह लोग मारे गए थे और 80 जख्मी हुए थे। इन धमाकों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हवाले की गई थी, जिसने बिहार, झारखंड आदि क्षेत्रों से दस मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे।

हिंदुस्तान (2 नवंबर) के अनुसार इंडियन मुजाहिदीन नामक आतंकी संगठन के रांची मॉड्यूल के प्रमुख हैदर अली उफ ब्लैक ब्यूटी ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने के लिए उनकी विभिन्न चुनावी सभाओं में सिलसिलेवार बम धमाके करने की साजिश रची थी। मगर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के कारण आतंकी अपने मंसूबे को कार्यान्वित करने में विफल रहे। पटना के गांधी मैदान में मोदी की हुंकार रैली में बम विस्फोट करने से पूर्व इन आरोपियों ने विभिन्न क्षेत्रों का मुआयना किया था। बमों को रांची से बस द्वारा पटना के मीठापुर बस स्टैंड पर लाया गया था। इसके बाद चार आरोपियों ने इन बमों को गांधी मैदान में विभिन्न स्थानों पर प्लांट किया था। एक आत्मघाती को मानव बम बनाए जाने के दौरान पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नम्बर 10 पर स्थित शौचालय में एक धमाका हुआ था, जिसमें आतंकी तारिक मारा गया था। जबकि दूसरा आतंकी इम्तियाज घटनास्थल से भागते हुए पकड़ा गया था। तलाशी के दौरान उसकी जेब से एक पर्चा मिला था, जिसके आधार पर जब रांची में छापा मारा गया तो उसके कमर से अनेक मोबाइल फोन नंबर पुलिस और जांच एजेंसी को प्राप्त हुए थे जो कि जांच में तुरूप का पत्ता सिद्ध हुए और इनके द्वारा पुलिस और जांच एजेंसियों को अन्य आतंकवादियों के सुराग मिले। इसके बाद पुलिस ने रांची की सिठियो बस्ती पर छापा मारा और वहां से अनेक आरोपियों को गिरफ्तार किया।

जांच एजेंसियों के अनुसार आतंकवादियों का सरगना हैदर अली और मुजीबुल्लाह पढ़ने में काफी तेज थे और वे दोनों यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इन लोगों ने बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनके तार विदेशों में स्थित गुप्तचर एजेंसियों से जुड़े हुए थे।

अवधनामा (29 नवंबर) में वकील अबु बकर सब्बाक का एक लेख प्रकाशित किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की सारी जांच व्यवस्था ही संदिग्ध है और इसके कारण बेगुनाहों को झूठे आरोपों में फंसाया जाता है और कई वर्ष जेल में बंद रखने के बावजूद उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश नहीं की जाती। लेख में कहा गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद संसद से पारित विशेष कानून के तहत की गई थी। मगर अधिकांश मामलों में यह जांच एजेंसी अपने कर्तव्यों को निभाने में विफल रही है। इस कानून के तहत इस बात का भी प्रावधान किया गया था कि आतंकवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए

विशेष न्यायालयों का गठन किया जाए ताकि सुनवाइ तेजी से हो सके। मगर 2013 में मंजर आलम नामक आरोपी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उसके खिलाफ 2014 में चार्जशीट दायर की गई थी। इस चार्जशीट में कुल 369 गवाह पेश किए जाने थे और 283 दस्तावेज भी पेश होने थे। मगर छह वर्ष गुजरने के बावजूद उसके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई नहीं हुई। यही कारण है कि उच्च न्यायालय को आरोपी को बरी करना पड़ा।

हज के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू

सहाफत (2 नवंबर) के अनुसार केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 2022 क लिए हज के कायक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि इस संबंध में मोबाइल ऐप के साथ-साथ देश भर के वक्फ बोर्ड के दफ्तरों में भी हज करने के इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन दे सकेंगे। देश के दस स्थानों से हज यात्रियों के विमान रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश है जहां से लगभग दो लाख मुसलमान हज यात्रा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। कोरोना महामारी के चलते दो वर्ष से सऊदी अरब ने अन्य देशों के हाजियों की हज यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। नकवी ने कहा कि हज यात्रा का सभी कार्य ऑनलाइन होगा। आवेदन देने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 रखी गई है। उन्होंने कहा कि हमारी नीति वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देने की है। इसलिए स्वदेशी सामान के साथ हाजी हज करने के लिए जाएंगे। इससे पूर्व हाजी चादर, तकिए, तौलिया, छतरी आदि विदेशी मुद्रा में सऊदी अरब से खरीदते थे। मगर वे अब भारतीय मुद्रा में ही जरूरी सामान खरीद सकेंगे। इससे उनके खर्च में 50 प्रतिशत तक की बचत होगी आर स्वदेशी तथा वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि हाजियों को हज रवाना होने से पूर्व उन स्थानों पर सभी आवश्यक सामान सरकार उपलब्ध करवाएगी जहां से वे विमान द्वारा प्रस्थान करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय हाजी सऊदी अरब में जो सामान खरीदते थे। उनमें से अधिकांश भारत का बना होता था

मगर वहां पर उन्हें दोगुने-तिगुने दामों पर खरीदना पड़ता था। सरकार की इस नई नीति से हाजियों को अरबों रुपये की बचत होगी। हज जाने के इच्छुक व्यक्तियां को कोरोना की दोनों वैक्सीन लगानी होगी और हज प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि हज यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है और हज यात्रा का कार्यक्रम तय करने से पूर्व इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, हज कमेटी और सऊदी अरब के दूतावास से काफी विचार-विमर्श किया गया है। इसके बाद हज मोबाइल ऐप को अपग्रेड किया गया है। इसका टैगलाइन 'हज ऐप इन योर हैंड' है। इस मोबाइल ऐप में सभी सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। हज यात्री जिन स्थानों से हज यात्रा करेंगे उनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और श्रीनगर शामिल हैं।

सियासत (26 अक्टूबर) के अनुसार उमरा के लिए बुकिंग के बाद दो सप्ताह का इंतजार समाप्त कर दिया गया है। सऊदी अरब की हज और उमरा मंत्रालय के अनुसार इस संबंध में कार्यक्रम में जरूरी संशोधन किया गया है। नमाज के लिए मस्जिद अल-हरम में विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके कारण उमरा करने के लिए निर्धारित तिथियों की संख्या में वृद्धि की गई है। काबा में पहली बार सामाजिक दूरी के बगैर जुमा की नमाज अदा की गई थी। नमाजियों की भारी संख्या को देखते हुए काबा के विस्तृत क्षेत्र में भी नमाज की व्यवस्था की गई है। काबा और मस्जिद-ए-नबवी को नमाजियों और यात्रियों के लिए खोलने का फैसला किया गया है। होटलों में प्रवेश पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वे भी हटा लिए गए हं।

इत्तेमाद (25 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी सरकार ने हाजियों और उमरा करने वालों पर कोरोना महामारी के कारण जो पाबंदियां लगाई थी उसे हटा लिया गया है। 17 अक्टूबर को पहली बार काबा शरीफ में खुले तौर पर नमाज अदा की गई। हालांकि नमाजियों के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। काबा के प्रमुख शेख अल-सुदैस ने काबा और मस्जिद-ए-नबवी में आने वाले नमाजियों के लिए सभी सुविधाओं का प्रबंध करने का सरकार को निर्देश दिया है। उन्होंने इस बात पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया है कि कोरोना महामारी का प्रकोप सऊदी अरब में नाम मात्र ही रहा है। उन्होंने इसका श्रेय सरकार को दिया, जिसने कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया था। समाचारपत्र ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि दो लाख से अधिक भारतीय हाजी अगले वर्ष हज यात्रा कर सकेंगे।

पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई

हाल ही में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

रोजनामा सहारा (29 अक्टूबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि टी-20 वर्ल्ड कप मैच में भारत पर पाकिस्तान की जीत के अवसर पर जश्न मनाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ट्वीट में कहा है कि 24 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान के बीच हुए वर्ल्ड कप मैच के दौरान शरारती तत्वों ने भारतीय टीम के खिलाफ न केवल अभद्र टिप्पणियां की बल्कि पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाकर देश में अशांति पैदा करने की कोशिश की है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक

इस संबंध में आगरा, बरेली, बदायूं और सीतापुर में पांच मुकदमे दर्ज करके सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. ओपी सिंह के अनुसार फैजगंज के रहने वाले नियाज ने अपने फेसबुक पेज पर पाकिस्तान का झंडा पोस्ट किया था और पाकिस्तान के पक्ष में कुछ नारे लिखे थे। उसे देशद्रोह आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पुनीत शाक्य ने इस संदर्भ में नियाज के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की थी।

रोजनामा सहारा (27 अक्टूबर) के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान टीम की जीत पर जश्न मनाने के आरोप में दो सरकारी मेडिकल कॉलेजों के कई छात्रों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किए हैं। 24 अक्टूबर की रात को दुबई में पाकिस्तान की भारत पर जीत पर कश्मीर घाटी में अनेक स्थानों पर लोगों ने जश्न मनाया था। इस संदर्भ में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दोनों मेडिकल कॉलेजों के कई छात्र-छात्राओं को खुशियां मनाते हुए पाया गया था। छात्रों को पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करते हुए भी दिखाया गया है। पुलिस के अनुसार शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के होस्टल में एमबीबीएस के विद्यार्थियों ने पाकिस्तान के पक्ष में न केवल नारेबाजी की बल्कि पटाखे भी फोड़े। एक अन्य समाचार के अनुसार जिला सांबा में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले कम-से-कम सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में और भी गिरफ्तारियां किए जाने की संभावना है।

अवधनामा (27 अक्टूबर) के अनुसार राष्ट्रीय बजरंग दल और डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों और महबूबा मुफ्ती एवं उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जम्मू मं विरोध प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रवींद्र रैना ने कहा है कि सरकार पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों को हरगिज नहीं बख्शेगी। पुलिस, सीआईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही हैं। इस देश के खिलाफ जो कोई नापाक हरकत करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हमारा समाज (30 अक्टूबर) के अनुसार आगरा में कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी के खिलाफ पीडीपी ने श्रीनगर में विरोध प्रकट करते हुए यह

मांग की है कि उन्हें शीघ्र-अति-शीघ्र रिहा किया जाए। महबूबा मुफ्ती ने इस संदर्भ में प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजकर उनसे अनुरोध किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि स्थिति न बिगड़े।

कौमी तंजीम (27 अक्टूबर) के अनुसार जम्मू कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने जश्न मनाने वाले छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वालों की निंदा की है और कहा है कि हम कश्मीर में रहते हैं तो हमसे वैचारिक मतभेद रखने वालों के साथ मिलजुलकर ही रहना होगा। भारत विरोधी या पाकिस्तान समर्थक होना कोई ऐसी समस्या नहीं है, जिसका समाधान तलाशा न जा सके। मगर जिस तरह से छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है उससे यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है।

सियासत (30 अक्टूबर) के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आगरा में पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने के आरोप में पकड़े गए तीन कश्मीरी छात्रों के साथ वकीलों और पुलिस के व्यवहार की निंदा की ह और आरोप लगाया है कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कॉलेज के प्रबंधक यह बयान दे चुके हैं कि लड़कों ने कोई नारा नहीं लगाया है।

इंकलाब (2 नवंबर) के अनुसार नेशनल कांफ्रेंस की महिला विंग ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले छात्रों की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए उग्र प्रदर्शन किया और कहा कि भाजपा यह चाहती है कि कश्मीरी छात्र शिक्षा प्राप्त न करें और वे पत्थरबाज बन जाएं। यही कारण है कि कश्मीर मं छात्रों के खिलाफ चार और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपना रूख नहीं बदला तो हमारे छात्र दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। भारत सरकार को चाहिए कि वह पाकिस्तान और कश्मीरियों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करे। दूसरी ओर भाजपा के एक पूर्व विधायक विक्रम सिंह रंधावा ने मांग की है कि इन कश्मीरी छात्रों की डिग्रियां जब्त की जाएं। सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पुनः नजरबंद कर दिया है।

इंकलाब (29 अक्टूबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस ने इंजोनियरिंग के तीन कश्मीरी छात्रों को न्यायालय में पेश किया है। इनके खिलाफ पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने का आरोप है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव ने तीनों छात्रों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये तीनों छात्र आगरा के बीचपुरी परिसर में स्थित इंजिनियरिंग के छात्र हैं। इनके नाम अरशद यूसुफ, इनायत अल्ताफ और शौकत अहमद बताए जाते हैं। जब उनकी हरकतों की जानकारी कॉलेज प्रबंधकों को मिली तो उन्हें निलंबित कर दिया। जब यह मामला हिंदू संगठनों की जानकारी में आया तो उन्होंने परिसर में पहुंचकर हंगामा किया और उनकी शिकायत पर पुलिस ने दोषी छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

इंकलाब (30 अक्टूबर) के अनुसार आगरा में गिरफ्तार किए गए शौकत अहमद के परिवारजनों ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने अपनी संपत्ति बेचकर इस लड़के को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था। अगर उससे कोई गलती हुई है तो हम उसकी ओर से माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से छात्रों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है।

टीवी चैनल **न्यूज18 इंडिया** (30 अक्टूबर) के अनुसार अलीगढ़ में पाकिस्तान टीम की जीत पर जश्न मनाने वाले एक युवक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम फारूक बताया जाता है और वह अकराबाद का रहने वाला है। पुलिस इस संदर्भ में जांच कर रही है।

एक अन्य समाचार के अनुसार राजस्थान के उदयपुर में पाकिस्तान की जीत पर खुशी जताने वाली एक शिक्षिका नफीसा अटारी को उसके स्कूल के प्रबंधकों ने निष्कासित कर दिया है। इसके बाद इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

जिन्ना पर अखिलेश यादव के बयान से हंगामा

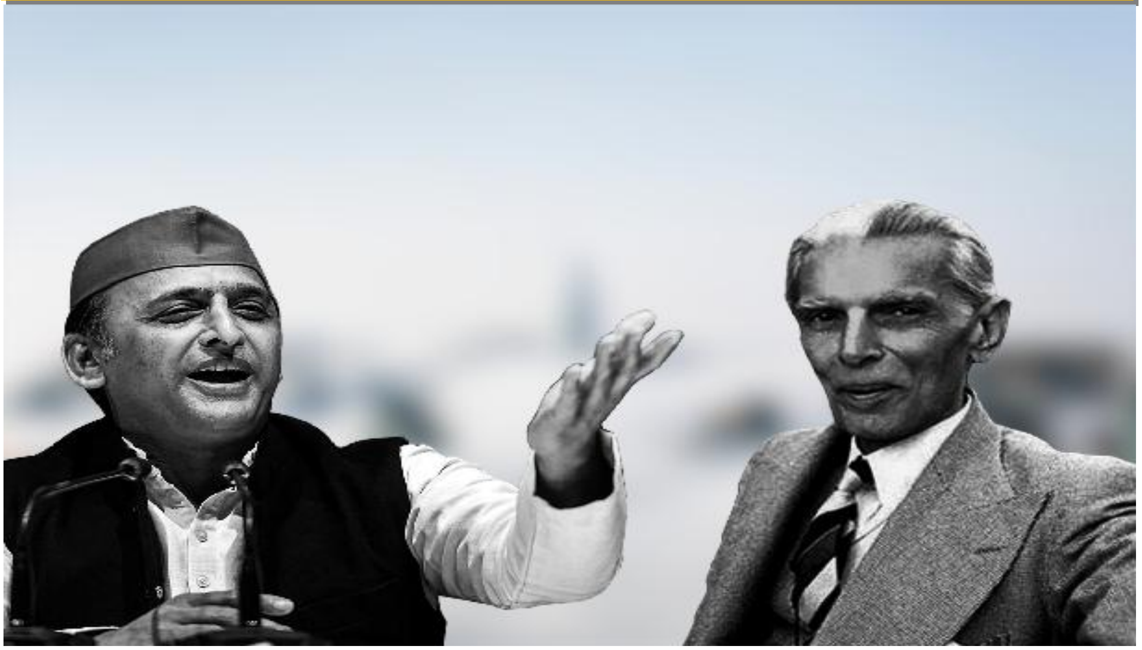

रोजनामा सहारा (2 नवंबर) के अनुसार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्रता संग्राम का नायक बताया था। हरदोई में 'समाजवादी विजय रथ' की रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्ना, गांधी और पटेल की सोच एक ही थी और जिन्ना ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल जमीन को पहचानते थे और वे ठोस फैसले लेते थे। इसलिए वे 'आयरन मैन' के नाम से जाने जाते थे। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ही संस्थान से बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने देश की आजादी के संग्राम में भाग लिया। भाजपा को अपना निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि आज देश को जात-पात और धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। वे लौहपुरुष सरदार पटेल ही थे जिन्होंने देश को विभाजित करने वाली सोच आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था।

समाचारपत्र न कहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा करके अखिलेश यादव विवादों में फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के इस बयान को शर्मनाक और तालिबानी मानसिकता का परिचायक बताया है। मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्ना की सरदार पटेल से तुलना लज्जाजनक है। इस देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव का यह बयान बेहद शर्मनाक है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी अखिलेश के इस बयान पर

जबर्दश्त प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि यह भाजपा और समाजवादी पार्टी क बीच गुप्त गठबंधन का संकेत है। भाजपा के इशारे पर अखिलेश यादव ने यह बयान हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से लड़वाने और आने वाले चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण करने के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो भाजपा मजबूत होती है। क्योंकि इन दोनों का आपस में गठजोड़ है।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी जिन्ना के बयान पर अखिलेश यादव को अपना निशाना बनाया है और कहा है कि अगर वे सोचते हैं कि उनके इस बयान से समाज का कोई वर्ग प्रसन्न होगा तो यह उनकी गलतफहमी है। भारतीय मुसलमानों को जिन्ना से कुछ लेना-देना नहीं है। हमारे पूर्वजों ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को खारिज कर दिया और हिंदुस्तान को अपना देश चुना। उन्होंने कहा कि उन्हें यह आशा नहीं थी कि अखिलेश यादव इतने अनाड़ी होंगे। उन्हें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए और पढ़ने की आदत डालनी चाहिए।

इंकलाब (2 नवंबर) के अनुसार भाजपा को निरंतर निशाना बनाने वाले अखिलेश यादव स्वयं ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उन्होंने एक रैली में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया था। उसके बाद उन पर चारां तरफ से हमला शुरू हो गया है। भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि अखिलेश यादव के इस बयान पर मुलायम सिंह यादव ने तो अपना माथा पीट लिया होगा। भाजपा के ही एक सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव को इस बयान के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने अखिलेश को निशाना बनाते हुए कहा है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के भीतर जो गुप्त गठजोड़ है उसी के कारण अखिलेश यादव फिक्स मैच खेल रहे हैं। देश को विभाजित करने वाले इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।

त्रिपुरा के घटनाक्रम की आड़ में मुस्लिम संगठन सक्रिय

बांग्लादेश में काफी दिनों से हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसकी प्रतिक्रिया त्रिपुरा में शुरू होने के कारण विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने त्रिपुरा में अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। 'पॉपुलर फ्रंट के योद्धा' नामक एक वेबसाइट ने यह दावा किया है कि त्रिपुरा में शरारती तत्वों द्वारा मुसलमानों पर जो हमले किए जा रहे हैं उनके खिलाफ भारत में जनमत जागृत करने के लिए देशव्यापी प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू किया जाएगा।

अखबार-ए-मशरिक (30 अक्टूबर) ने यह दावा किया है कि पॉप़लर फ्रंट ने असम और त्रिपुरा में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और शाखाओं का जाल फैलाया जा रहा है। हाल ही में त्रिपुरा की राजधानी अगरतल्ला और एक दर्जन अन्य स्थानों पर पॉपुलर फ्रंट ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का आयोजन किया था। पॉपुलर फ्रंट की गतिविधियां पहले केरल तक ही सीमित थी मगर दो वर्ष पूर्व इसके मुख्यालय को कोझीकोड से दिल्ली लाया गया था। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ इस संगठन की ओर से उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में जोरदार प्रदर्शन किए गए थे, जिसके कारण इन क्षेत्रों में उसका मकड़जाल तेजी से फैला है।

हमारा समाज (29 अक्टूबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के अध्यक्ष नजर आलम ने पटना में एक प्रेस-विज्ञप्ति जारी करके भारत सरकार पर इस बात के लिए दबाव

डाला है कि वह त्रिपुरा में मुसलमानों की जान व माल की संरक्षण की व्यवस्था करे। उन्होंने मस्जिदों और मुस्लिम आबादी पर हमले करने का आरोप लगाया है और यह दावा किया है कि इन दंगों के पीछे विश्व हिंदू परिषद का हाथ है।

मुंबई उर्दू न्यूज (30 अक्टूबर) के अनुसार त्रिपुरा में मस्जिदों पर हमलों के खिलाफ त्रिपुरा भवन के बाहर वेल्फेयर पार्टी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट एवं विभिन्न छात्र संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री मोदी तथा अमित शाह के साथ-साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पुलिस ने इस प्रदर्शन के सिलसिले में 200 लोगों को हिरासत में लिया था जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया।

मुंबई उर्दू न्यूज (31 अक्टूबर) में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार त्रिपुरा की घटनाआं के बारे में वहां की उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया है और सरकार से पूछा है कि उसने हिंसा को रोकने क लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं? उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में सरकार से शपथपत्र दाखिल करने की मांग की है।

अखबार-ए-मशरिक (29 अक्टूबर) के अनुसार पश्चिम बंगाल के विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिविल राइट्स की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्र सरकार और त्रिपुरा सरकार से मांग की है कि मुसलमानों और मस्जिदों को निशाना बनाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

अवधनामा (28 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सरकार ने यह दावा किया है कि त्रिपुरा में अब स्थिति शांत है और 150 मस्जिदों को पुलिस की सुरक्षा प्रदान की गई है और कई शरारती तत्वों को गिरफ्तार किया गया है। समाचारपत्र के अनुसार जमीयत उलेमा का दावा है कि त्रिपुरा में कुछ मस्जिदों पर हमले किए गए और वहां पर भगवा झंडे लहराए गए।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 अक्टूबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर उनसे यह मांग की है कि राज्य में मुसलमानों और मस्जिदों को सुरक्षा प्रदान की जाए।

सियासत (31 अक्टूबर) के अनुसार कुछ शरारती तत्व पश्चिम बंगाल में साम्प्रदायिक दंगे करवाने के लिए फर्जी वीडियो वायरल कर रहे हैं। राज्य सरकार ने ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है।

गुरुग्राम में नमाज पढ़ने पर विवाद

इंकलाब (30 अक्टूबर) के अनुसार गुरुग्राम में खुल स्थान पर मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने का विवाद दिन-प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि मुसलमानों को नमाज मस्जिदों के अंदर ही अदा करनी चाहिए। जुमा के दिन नमाज में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने 30 व्यक्तियों को हिरासत में लिया था। गत तीन वर्ष से सार्वजनिक स्थानों और पार्कों मं नमाज अदा करने के प्रश्न पर मुसलमानों और स्थानीय निवासियों में काफी विवाद चल रहा है। गत सप्ताह भी जुमा के दिन काफी हंगामा हुआ था। इस क्षेत्र के निवासियों ने प्रशासन को एक ज्ञापन देकर यह मांग की थी कि पार्कों में मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति न दी जाए क्योंकि इससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है।

प्रशासन ने तीन वर्ष पूर्व जिला गुरुग्राम में 37 स्थानों को नमाज अदा करने के लिए निर्धारित किया था। गुरुग्राम में कारखाने काफी हैं जहां मुसलमान काम करते हैं। नगर का काफी विस्तार हुआ है। इसलिए नए सेक्टरों में मस्जिदें आदि की व्यवस्था नहीं हं। मुसलमानों को यह शिकायत है कि जब भी वे खुले में नमाज अदा करते हैं तो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता उनकी नमाज में बाधा उत्पन्न करते हैं। स्थानीय नागरिकों का शुरू से ही इस बात का आग्रह रहा है कि मुसमलानों को नमाज अपनी मस्जिदों के अंदर ही अदा करनी चाहिए। शुरू में भाजपा सरकार मुसलमानों को खुले में नमाज अदा करने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं थी मगर बाद में मुस्लिम समाज के दबाव के कारण खट्टर सरकार ने मुसलमानों की नमाज के लिए 37 स्थान निर्धारित किए थे।

विश्व

बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे

दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के दावों के बावजूद थम नहीं रहा है। बड़ी अजीब बात है कि त्रिपुरा पर विधवा विलाप करने वाले उर्दू समाचारपत्रों ने बांग्लादेश की घटनाओं का लगभग नजरअंदाज किया है। किसी भी भारतीय मुस्लिम नेता ने बांग्लादेश की घटनाओं की खुले रूप से निंदा नहीं की है और न ही किसी समाचारपत्र ने इस संबंध में कोई संपादकीय ही लिखा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (17 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगों की शुरुआत एक दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान की पुस्तक रखे जाने से शुरू हुई थी। इस घटना की आड़ लेकर इस बात का प्रचार किया गया कि कुरान की जानबूझकर बेइज्जती की गई है। सरकारी सूत्रों ने इन झड़पों में पहले दिन दो व्यक्तियों के मारे जाने का दावा किया था। जबकि फ्रांसीसी संवाद समिति 'एएफपी' के अनुसार इन झड़पों में कम-से-कम छह लोग मारे गए थे। इसके बाद बांग्लादेश के 12 जिलों में दंगों की ज्वाला भड़क उठी। उत्तेजित मुसलमानों की भीड़ ने दुर्गा पूजा के पंडालों पर हमले किए और उनमें आग लगा दी। नोवाखाली में इस्कॉन मंदिर में घुसकर उग्र भीड़ ने वहां के प्रबंधक पार्थ दास की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। नोआखली में ही बेगमगंज नामक कस्बे में दर्जनों मंदिरों को आग लगाने के बाद ध्वस्त कर दिया। बांग्लादेश के गृहमंत्री असदुज्जमां खान ने कहा है कि दंगाईयों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। पहले चरण में 90 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि चटगांव और ढाका में भी उग्र भीड़ द्वारा हिंदू बस्तियों, मंदिरों और दुर्गा पंडालों को अपना निशाना बनाया जा रहा है। उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ा। नागरिकों की

रक्षा के लिए अर्द्धसैनिक ट्कड़ियों को लगाया गया है और पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया ह। पदर्शनकारी भारत और प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। सरकारी तौर पर 80 मंदिर उग्र भीड़ का निशाना बने हैं और 200 से अधिक हिंदू जख्मी हुए हैं।

इसी समाचारपत्र ने 18 अक्टूबर के अंक में यह दावा किया है कि हिंदू विरोधी दंगे बांग्लादेश के 30 से अधिक जिलों में फैल गए हैं। चांदपुर, शंकरग्राम, नोआखाली, सरहट, मौलवी बाजार, कुरिग्राम, मुंशीगंज, किशोरगंज और फेनी में उग्र भीड़ मंदिरों और हिंदू बस्तियों को अपना निशाना बना रही है। डेढ़ सौ के लगभग हिंदू मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई है। उग्र भीड़ को नियंत्रित करते हुए 40 से अधिक पुलिसवाले जख्मी हुए हैं। फेनी के पुलिस अधीक्षक खांडाकर नुरुन्नबी ने यह स्वीकार किया है कि उग्र भीड़ हिंदू मंदिरों और पूजा पंडालों को अपना निशाना बना रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर उत्तेजक पोस्ट डालने वाले 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। चांदपुर में पुलिस की गोली से छह लोग मारे गए हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश पूजा परिषद के अध्यक्ष मिलन कांति दत्ता ने आरोप लगाया है कि पुलिस जानबूझकर दंगाईयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

शासक दल अवामी लीग के महासचिव उबेदुल कादिर ने यह स्वीकार किया है कि ये हमले पूर्वनियोजित हैं। जब लोगों ने पुजारी पार्थ दास के शव को लेकर जुलूस निकाला तो उस जुलूस पर उग्र भीड़ ने हमला किया और कई लोगों की हत्या कर दी। बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध क्रिस्चियन एकता परिषद के सचिव ने कहा है कि अगर सरकार दंगों पर काबू पाने में विफल रहती है तो हम अनिश्चितकाल के लिए धरना देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जिहादी एक सुनियोजित योजना के तहत ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं जिससे भयभीत होकर अल्पसंख्यक बांग्लादेश से पलायन करें। हिंदू परिषद के महामंत्री राणा दास गुप्ता ने कहा है कि हालांकि प्रधानमंत्री शेख

हसीना देश में सद्भावनापूर्ण वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रही हैं मगर उनके कई सहयोगी उनके प्रयासों में पलीता लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में एक वर्ष पूर्व जो हिंदू जनसंख्या दस प्रतिशत थी वह अब कम होकर सात प्रतिशत ही रह गई है।

रोजनामा सहारा (22 अक्टूबर) के अनुसार पुलिस ने कोमिल्ला में दुर्गा पूजा पंडाल में फटे हुए कुरान को रखने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इकबाल हुसैन नामक यह व्यक्ति 30 वर्ष का है। इस घटना के बाद 13 अक्टूबर से कुरान के तथाकथित अपमान को लेकर बांग्लादेश के सभी जिलों में हिंदू मंदिरों और हिंदू बस्तियों पर हमले किए गए थे और हिंदू बस्तियों को लूटा गया था। पुलिस के दावे के अनुसार इस संदर्भ में 72 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 450 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश भर के मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है।

इंकलाब (16 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दंगाईयों को यह चेतावनी दी है कि उन्हें किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। मगर इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह अपने देश में दंगाईयों के खिलाफ सख्ती से निपटे। भारत में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो कि बांग्लादेश को प्रभावित करे और हमारे हिंदुओं को कठिनाईयों का सामना करना पड़े। दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाकेश्वरी मंदिर में होने वाली दुर्गा पूजा के अवसर पर हिंदुओं को बधाई देते हुए यह बात कही। समाचारपत्र के अनुसार बांग्लादेश के 22 जिलों में अर्द्धसैनिक दस्ते भारी संख्या में तैनात किए गए हैं।

रोजनामा सहारा (30 अक्टूबर) के अनुसार इस्कॉन मंदिर के प्रमुख चारू चंद दास ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है इसलिए इस्कॉन ने विश्व के 150 देशों में फैले

हुए अपने समर्थकों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने अपने देश में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। उन्होंने यह भी कहा है कि शेख हसीना के शासनकाल में हिंदुओं की संपत्ति अवैध रूप से जब्त की गई और उन पर सुनियोजित हमले किए गए। उन्होंने कहा है कि हाल के दंगों में जो हिंदू मंदिर ध्वस्त किए गए हैं सरकार उनकी मरम्मत कराए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने में गंभीर नहीं है। इन दंगों की तैयारी बहुत समय से चल रही थी। मगर गुप्तचर एजेंसियों ने जानबूझकर इनको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

दैनिक सियासत (30 अक्टूबर) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर मुस्लिम अतिवादियों के हमलों की निंदा करते हुए वहां की सरकार से अपील की है कि वह ऐसे दंगाई तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। संघ ने बांग्लादेशी हिंदू समाज को यह आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित पूरा हिंदू समाज इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा हुआ है। एक प्रस्ताव में इस बात पर चिंता प्रकट की गई है कि देश के विभाजन के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या निरंतर घट रही है। देश के विभाजन के समय बांग्लादेश में जो हिंदू आबादी 28 प्रतिशत थी वह अब घटकर आठ प्रतिशत से भी कम रह गई है।

इस्लामिक स्टेट की शिया मुसलमानों को निशाना बनाने की धमकी

इंकलाब (19 अक्टूबर) के अनुसार अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों के कत्लेआम का सिलसिला थम नहीं रहा है। सुन्नी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि शिया मुसलमान बेहद खतरनाक हैं। उन्हें दुनियाभर में निशाना बनाया जाएगा। खामा प्रेस के अनुसार इस्लामिक स्टेट इराक और सीरिया के साप्ताहिक समाचारपत्र ने यह धमकी दी है कि शियाओं को पहले चरण में बगदाद से खुरासान तक निशाना बनाया जाएगा। आईएसआईएस का खुरासान चैप्टर तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान में शांति स्थापना की दिशा में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस्लामिक स्टेट अब तक अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों की तीन प्रमुख मस्जिदों को अपना निशाना बनाकर ढ़ाई सौ से भी अधिक मासूमों की हत्या कर चुका है और उसने इन हत्याओं की जिम्मेवारी भी ली है। 8 अक्टूबर को अफगानिस्तान के कंधार में एक मस्जिद पर हमला करके 100 से अधिक शियाओं को नमाज पढ़ते हुए निशाना बनाया गया था। रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतीन ने यह दावा किया है कि अफगानिस्तान के उत्तरी भाग में 2000 से अधिक आईएसआइएस के आतंकी मौजूद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आईएसआईएस के आतंकवादी शरणार्थियों के रूप में विभिन्न देशों में दाखिल होने का प्रयास कर रहे हैं। तालिबान ने रूस के इस दावे का खंडन किया है।

राजनामा सहारा (17 अक्टूबर) के अनुसार कंधार की एक शिया मस्जिद में आईएसआईएस ने आत्मघाती हमला किया, जिसमें कम-से-कम 50 लोग मारे गए और दर्जनो घायल हुए। आईएसआईएस ने अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए एक बयान जारी करके इस घटना की जिम्मेवारी ली है और यह धमकी दी है कि इन हमलों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया है कि तालिबान के काबुल में कब्जे के बाद वे चार बार शियाओं को अपना निशाना बना चुके हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि शिया सुन्नी को आपस में लड़वाने का जो प्रयास चल रहा है उसे हम विफल करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कंधार की मस्जिद में तीन जगहों पर बम विस्फोट हुए थे। हैरानी की बात यह है कि इन सभी हमलों में शियाओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। मुजाहिद ने दावा किया है कि हम आईएसआईएस के आतंकियों को हर जगह से खोजकर उनका नामोनिशान मिटा देंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में शियाओं के कत्लेआम की निंदा की है और इस्लामिक देशों से अपील की है कि वे इस्लाम दुश्मनों की हरकतों की निंदा करें।

इंकलाब (28 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिका के रक्षा सचिव ने चेतावनी दी है कि

इस्लामिक स्टेट के आतंकी अगले छह महीने में अमेरिका में कोई बड़ी हिंसक कार्रवाई कर सकते हैं इसलिए अमेरिका को इस संबंध में सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अलकायदा से भी ज्यादा खतरनाक इस्लामिक स्टेट है और हमें इराक और सीरिया की बजाय अफगानिस्तान से ज्यादा खतरा है। हम इस खतरे का सामना करने के लिए सभी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में सक्रिय इस्लामिक आतंकी गुटों को विदेशों से हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान में चीन, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने आरोप लगाया है कि अमेरिका इस्लामिक स्टेट के माध्यम से अफगानिस्तान में खून की होली खेल रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए सभी देशों को एकजुट होना चाहिए।

ब्रिटिश सांसद की जिहादी द्वारा हत्या

इंकलाब (16 अक्टूबर) के अनुसार ब्रिटेन में सत्तारूढ़ दल के एक सांसद सर डेविड एमेस पर एक जिहादी ने गिरजाघर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस जांच के अनुसार आक्रमणकारी का नाम अली हर्बी अली बताया जाताा है और वह सोमालिया का मूल निवासी है। 69 वर्षीय ब्रिटिश सांसद पर उसने निरंतर चाकू से कई बार वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। भीड़ ने आक्रमणकारी को मौके पर ही पकड़ लिया और उसके कब्जे से चाकू भी बरामद किया गया है। आक्रमणकारी की उम्र 25 वर्ष बताई जाती है और उसका संबंध अतिवादी इस्लामिक संगठनों से बताया गया है। इन दिनों यूरोप के विभिन्न देशों में इस्लामिक आतंकवाद तेजी से फैल रहा है। फ्रांस और जर्मनी ने तो

विशेष कानून पारित करके विदेशों से आने वाले मुस्लिम शरणार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप पर हमला

इंकलाब (23 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के एक कैंप पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। उन्होंने एक मदरसे पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें सात व्यक्ति मौके पर मारे गए और दो दर्जन से अधिक घायल हो गए। पुलिस ने आक्रमणकारियों की तलाश शुरू कर दी है। समाचारपत्र के अनुसार यह घटना बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित रोहिंग्या शरणार्थियों के एक शिविर में हुई। पुलिस के अनुसार आक्रमणकारियों की संख्या एक से अधिक

थी। दो दिन पूर्व भी इसी रोहिंग्या शिविर पर कुछ लोगों ने हमला किया था, जिसमें चार लोग मारे गए थे। पुलिस ने एक आक्रमणकारी को मौके पर पकड़कर उससे एक पिस्तौल और चाकू भी बरामद किया था। बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंपों में लगभग नौ लाख शरणार्थी रह रह हैं जिन्होंने म्यामार में रोहिंग्याओं के खिलाफ की गई सैनिक कार्रवाई के बाद वहां से पलायन किया था। शरणार्थियों का सबसे बड़ा शिविर कॉक्स बाजार में स्थित है, जिसमें 5 लाख शरणार्थी रहते हैं। वे चार वर्ष पूर्व म्यामार से भागकर यहां आए थे। हाल ही में इस शिविर के दो लाख से अधिक लोगों को संयुक्त

राष्ट्र संघ की शरणार्थी शाखा के सहयोग से बांग्लादेश के समीप एक टापू में आबाद किया गया है। अधिकांश शरणार्थी नए स्थान पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं।

चीन द्वारा अफगानिस्तान में पूंजी निवेश की तैयारी

हमारा समाज (16 अक्टूबर) के अनुसार तालिबान के उप सूचना मंत्री जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि चीन ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर के पूंजी निवेश की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने 'वॉयस ऑफ अमेरिका' की प्रतिनिधि आयशा तंजोम के साथ वार्तालाप करते हुए यह दावा किया कि विश्व भर के देशों ने अफगानिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यदि हमारे फ्रीज की गई पूंजी को रिलीज कर देता है तो हमें किसी भी विदेशी सहायता की जरूरत नहीं होगी और हम अपने पांव पर खड़े हो सकेंगे। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों का उल्लेख करने पर उन्होंने कहा कि विदेशी सूत्र आईएसआईएस वालों की संख्या जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं। हम इस स्थिति में हैं कि उनकी कमर तोड़ सकें। उन्होंने दावा किया कि तालिबान ने इस्लामिक स्टेट से संबंधित 200 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके अनेक ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने की स्थिति में हैं।

हमारा समाज में ही प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव जेन साकी ने इस समाचार का खंडन किया है कि चीन अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का पूंजी निवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है उसको देखते हुए इस बात की संभावना नहीं है कि वह अफगानिस्तान में कोई भारी पूंजी निवेश कर सके। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने भी अफगानिस्तान में चीन द्वारा पूंजी निवेश किए जाने के दावे पर संदेह व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अगर चीन अफगानिस्तान में पूंजी निवेश करता है तो वह यह भी आशा करेगा कि उसे प्रत्येक वर्ष करोड़ों डॉलर वहां से वापस प्राप्त हो जो कि अफगानिस्तान की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए संभव नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव पर अभी तक चीन ने तालिबान को सिर्फ 31 लाख डॉलर ही उपलब्ध कराए हैं। जब तक अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिलती उसे विदेशी पूंजी निवेश की आशा नहीं करनी चाहिए।

सूडान में सैनिक विद्रोह

इंकलाब (26 अक्टूबर) के अनुसार सूडान में सैनिक विद्रोह के बाद प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है और अनेक उच्चाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया के अनुसार सेना ने अनेक मंत्रियों, खार्तूम के गवर्नर और अन्य उच्चाधिकारियों को हिरासत में ले लिया है। सूडान के सूचना मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि सेना ने कई दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। सेना ने नागरिकों को कहा है कि वे अपने घरों से बाहर न आएं। मगर इसके बावजूद अनेक नगरों में लोग राष्ट्रीय ध्वज के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी खार्तूम में भी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। प्रदर्शनकारियों ने सैनिक मुख्यालय को घेरे में ले लिया है। गिरफ्तार किए गए प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को किसी अज्ञात स्थान पर हिरासत में रखा गया है। प्रधानमंत्री हमदोक ने इस सैनिक क्रांति का समर्थन करने से इंकार कर दिया है और जनता से अनुरोध किया है कि वे अपने नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन जारी रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ में सूडान के प्रतिनिधि ने सैनिक विद्रोह को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि जिस तरह से पुरानी सरकार के प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हिरसात में लिया गया है वह परेशानी की बात है। उन्होंने सेना से यह अपील की है कि वह गिरफ्तार किये गए सभी लोगों को रिहा कर दे। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने भी सूडान की घटना पर चिंता प्रकट की है। अरब लीग के महासचिव ने सूडान के सभो पक्षों से अपील की है कि वे अगस्त 2019 में हुए समझौते का पालन करें और आपसी विवादों को बातचीत से हल करे। क्योंकि आपसी झगड़े देश के हित में नहीं हैं।

दूसरी ओर **रोजनामा सहारा** (26 अक्टूबर) के अनुसार सूडानी सेना के एक जनरल

हनाफी अब्दुल्ला ने यह दावा किया है कि सेना ने देश में असली लोकतंत्र की स्थापना के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। 'अल-अरेबिया' न्यूज चैनल को इंटरव्यू देत हुए उन्होंने कहा है कि सेना यह प्रयास करेगी कि देश में एक सिविलियन सरकार का गठन किया जाए और स्वतंत्र वातावरण में चुनाव करवाए जाएं। उन्होंने दावा किया है कि जो सैनिक परिषद बनाई गई है उसके प्रमुख अब्दुल फतह अल-बुरहान देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। इससे पूर्व जनरल अल-बुरहान ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वे अपने मंत्रिमंडल को भंग कर दें। मगर उन्होंने इस सुझाव को मानने से इंकार कर दिया था। पिछले महीने भी सूडान में सैनिक क्रांति का असफल प्रयास किया गया था। अमरिका ने कहा है कि सूडान में जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन हुआ है और जिस तरह से ताकत के बल पर सत्ता पर कब्जा किया गया है वह अमेरिकी नीति के खिलाफ है।

मुंबई उर्दू न्यूज (29 अक्टूबर) के अनुसार सूडान के सरकारी टेलीविजन के अनुसार सेना के कमांडर इन चीफ अल-बुरहान ने विदेशों में नियुक्त छह सूडानी राजदूतों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है, जिनको बर्खास्त किया गया है उनमें अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, कतर, चीन और फ्रांस के राजदूत शामिल हैं। जनविरोध को दबाने के लिए सेना मैदान में कूद पड़ी है और विरोध करन वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जनाक्रोश को कम करने के लिए बर्खास्त प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह हमदोक को कैद खाने से वापस उनके घर भेज दिया गया है। हालांकि उनके घर के बाहर सेना का कड़ा पहरा है। सेना विरोधियों को दबाने का प्रयास कर रही है। 2019 में राष्ट्पति उमर अल-बशोर की सरकार का तख्ता पलट दिया था और एक अस्थाई सरकार की स्थापना की गई थी, जिसने यह तय किया था कि एक वर्ष के भीतर देश में चुनाव करवाए जाएंगे और सत्ता पुन: सिविलियन सरकार को सौंप दी जाएगी। मगर इस समझौते का पालन नहीं हो सका।

1956 में सूडान को विदेशी गुलामी से मुक्ति मिली थी मगर राजनीति में सेना का दखल बढ़ गया था। दो वर्ष बाद 1958 में चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल इब्राहिम अबौद ने एक खूनी क्रांति के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया था। 1964 में जनाक्रोश के कारण सेना को सत्ता छोड़नी पड़ी। मगर सिविलियन सरकार ज्यादा दिन टिक न सकी। पांच वर्ष बाद ही सेना ने पुन: सत्ता पर कब्जा कर लिया। 1985 में एक अन्य गुट ने सेना की सहायता से पुराने सैनिक अधिकारियों को सत्ता से बाहर कर दिया और खुद सत्ता संभाल ली। इसके बाद देश में चुनाव हुए और सत्ता सिविलियन सरकार अल सादिक अल-महदी नामक प्रधानमंत्री के हाथ लगी। मगर तीन वर्ष बाद 1989 में ब्रिगेडियर उमर अल-बशीर के नेतृत्व में सेना ने फिर सत्ता पर कब्जा कर लिया। 30 वर्ष तक उमर अल-बशीर सत्ता में रहे। मगर बाद में 2019 में हुए विद्रोह के बाद सेना और सिविलियन ने मिलकर कार्यकारी परिषद का गठन किया।

नाइजीरिया में मस्जिद पर हमले में 18 मरे

सियासत (27 अक्टूबर) के अनुसार उत्तरी नाइजीरिया में एक मस्जिद में नमाजियों पर सशस्त्र गिरोह ने हमला करके कम-से-कम 18 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना नाइजीरिया के मज़कुका कस्बा में हुई। आक्रमणकारियों का संबंध खानाबदोश फोलानी खानदान से बताया जाता है। इस हमले के बाद आक्रमणकारी फरार हो गए। नाइजीरिया में पिछले एक दशक से विभिन्न

कबीलों के बीच गृहयुद्ध चल रहा है। इनमें से कुछ कबीलों को अलकायदा से संबंधित जिहादी संगठन अल शबाब का समर्थन भी प्राप्त है। जहां यह घटना हुई है वह राजधानी से 270 किलोमीटर दूर है।

इससे पूर्व **रोजनामा सहारा** (25 अक्टूबर) के अनुसार एक सशस्त्र गिरोह ने नाइजीरिया की एक जेल पर हमला किया। इस गिरोह ने पहले बमों से जेल की चहारदीवारी को उड़ा दिया और इसके बाद उन्होंने जेल में घुसकर पुलिस को बंधक बना लिया और इस जेल में बंद 800 से अधिक कैदियों को रिहा कर दिया। सेना ने सर्च

अभियान चलाया, जिसके तहत ढ़ाई सौ कैदियों को पुनः हिरासत में लिया गया। सेना हमला करने वाले गिरोह की तलाश कर रही है।

मिस्र में आपातकाल समाप्त

इंकलाब (28 अक्टूबर) के अनुसार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी ने चार वर्ष पूर्व लगाए गए आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की है। उन्होंने यह दावा किया है कि यह आपातकाल आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए लगाया गया था। हालांकि उनके विरोधियों का दावा है कि इस आपातकाल का लाभ उठाकर अल-सिसी ने अपने हजारों विरोधियों को जेल में डाल दिया।

समाचारपत्र के अनुसार अप्रैल 2017 में मिस्र के कुतुबी गिरजाघरों में अतिवादी इस्लामिक संगठन की ओर से बम विस्फोट किए गए थे, जिनमें कई सौ लोग मारे गए थे। इन धमाकों की जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेट से संबंधित एक गुट ने ली थी। इन धमाकों के तीन महीने के बाद देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। सरकार का दावा है कि यह आपातकाल आईएसआईएस के आतंकियों से देश की रक्षा करने के लिए लगाई गई थी। इसका लाभ उठाकर जनता को उनके मूलभूत नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था और मीडिया पर सेंसर लगा दिया गया था। देश भर में जनसभाएं और प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देश से आपातकाल हटाए जाने पर टिप्पणी करते हुए मिस्र के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने राष्ट्रपति के इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि राजनीतिक द्वेष के कारण सैकड़ों विरोधियों क खिलाफ जो मुकदमे अदालत में चल रहे हैं उन पर इस घोषणा का कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार चोर दरवाजे से सारी सत्ता अपने हाथों में रखना चाहती है और लोकतंत्र को दबाना चाहती है।

तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का कड़ा कदम

कौमी तंजीम (25 अक्टूबर) के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तयब एर्दोगान ने अमेरिका सहित दस पश्चिमी देशों के राजदूतों को अपने देश से निकल जाने का आदेश दिया है। इन राजदूतों ने सामाजिक कार्यकर्ता उस्मान कवला को कैद से रिहा करने पर जोर दिया था। हैरानी की बात यह है कि जिन सात देशों के राजदूतों को तुर्की से निष्कासित करने का आदेश दिया गया है उनमें सात का संबंध नाटो देशों से है। अगर उनको तुर्की से निकाला जाता है तो यह तैयब इर्दोगान के 19 वर्षीय सत्ताकाल के दौरान पहली बार पश्चिमी देशों से उनके गंभीर मतभेदों की शुरुआत होगी। नागरिक अधिकारों के आंदोलनकारी उस्मान कवला गत चार वर्षों से जेल में बंद हैं। 2013 में उन पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने विदेशियों के इशारे पर तुर्की में प्रशासन के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करवाए थे। 2016 में तुर्की में असफल विद्रोह के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। 18 अक्टूबर को कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और अमेरिका के राजदूतों ने एक संयुक्त ज्ञापन में उस्मान कवला को फोरन रिहा करने पर जोर दिया था। इस पर इन सभी राजदूतों को तुर्की के विदेश मंत्रालय में तलब करके उनके बयान को तुर्की के आंतरिक मामलों मं हस्तक्षेप करने की संज्ञा दी थी।

तैयब इरदोगान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि किसी भी विदेशी शक्ति को हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इन दस राजदूतों ने जो कुछ किया है उसे सहन नहीं किया जा सकता। इसलिए यह जरूरी है कि वे तुर्की से बोरिया-बिस्तर बांधकर चले जाएं। नार्वे की सरकार ने कहा है कि हम तुर्की के लोगों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड ससोली ने कहा है कि दस देशों के राजदूतों को तुर्की से निष्कासित करना तुर्की सरकार की तानाशाही है जिसे सहन नहीं किया जा सकता।

कौमी तंजीम ने 27 अक्टूबर के अपने संपादकीय में इर्दोगान को सलाह दिया है कि वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। समाचारपत्र ने कहा है कि जहां तक इर्दोगान के दृष्टिकोण का संबंध है वे इस मामले में साफ हैं कि जो विदेशी सरकारें तुर्की से दोस्ती करना चाहती हैं उन्हें उसके मामलां में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और जो इस सिद्धांत को नहीं मानते उन्हें वहां बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

अरब इत्तेहाद का यमन में फौजी ऑपरेशन

रोजनामा सहारा (22 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी अरब और उसके सहयोगियों ने यमन की राजधानी साना में फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सऊदी अरब ने दावा किया है कि यमन में हूती विद्रोही विदेशी इशारे पर सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं। अब इसे सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह दावा किया कि इस अभियान में इस बात का प्रयास किया जाएगा कि नागरिकों को कोई परेशानी न हो। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने अमेरिकी राजदूत से अनुरोध किया है कि वे ईरान पर इस बात के लिए दबाव डालें कि वह हूतियों की सहायता करना बंद कर दे। सऊदी अरब सुरक्षा परिषद ने हूतो मिलिशिया की ओर से सऊदी अरब पर किए जा रहे हमलों की निंदा की है। यमन में हूतियों की गतिविधियों के कारण लोग भूखे मर रहे हैं।

सियासत (21 अक्टूबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन यूनिसेफ के आकड़ों के अनुसार यमन में हूती विद्रोहियों के कारण दस हजार बच्चे या तो मारे जा चुके हैं या अपंग हो गए हैं। यमन में पिछले पांच वर्षों से युद्ध जारी है जहां ईरान के समर्थक हूती विद्रोही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार से युद्ध में लगे हुए हैं। गृह युद्ध के कारण 17 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और एक करोड़ 10 लाख लोग भुखमरी का शिकार हैं। बीस लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।

इंकलाब (26 अक्टूबर) के अनुसार यमन में मारिब सूबा में हूतियों की बमबारी के कारण मरने वालों की संख्या 40 तक पहुंच चुकी है। मरने वालों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। यमन के सूचना मंत्री मुअम्मर अल-इरियानी का दावा है कि इस हमल में ईरान में बनी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। विद्रोहियों ने जानबूझकर मस्जिदों, मदरसों और नागरिकों को अपना निशाना बनाया। यमनी सरकार ने विश्व के देशों से यह मांग की है कि व इस मामले में हस्तक्षेप करं।

इंकलाब (28 अक्टबर) के अनुसार अरब एलायंस का दावा है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था ने बारूद से लदे हुए दो ड्रोन तबाह कर दिए हैं। इनका निशाना आभा हवाई अड्डा और नजरान शहर था। यमनी सरकार की जवाबी कार्रवाई में 85 हूती विद्रोही मारे गए और नौ सैनिक वाहन तबाह हो गए। सऊदी एलायंस की फौजों ने दो दिन में हूतियां पर 21 सैनिक कार्रवाईयां कीं जिसमें 105 हूती मारे गए। एलायंस ने यह भी दावा किया है कि मारिब में सेना की कार्रवाई मं 92 से अधिक हूती मारे गए हैं और इनके कब्जे से ईरान के बने हुए हथियार बरामद हुए हैं।

चीन की कुरान दुश्मनी

मुंबई उर्दू न्यूज (17 अक्टूबर) के अनुसार विख्यात कंपनी एप्पल ने इस बात की पुष्टि की है कि चीन सरकार के दबाव पर उसने कुरान की ऐप को बंद कर दिया है। कुरान मजीद नामक ऐप दुनिया भर में ऐप स्टोर पर उपलब्ध है और उसकी रिव्यूवर की संख्या 50 करोड़ से भी अधिक बताई जाती है। मगर चीन सरकार के दबाव पर उसे डिलीट कर दिया गया है। जब चीन सरकार से इस संबंध में संपर्क किया गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हालांकि इस्लाम को एक धर्म के रूप में मान्यता देती है परंतु उस पर मुसलमानों के उत्पीड़न का आरोप प्रायः लगता रहा है।

मौलाना महमूद मदनी प्रभावी नेताओं की सूची में

हमारा समाज (20 अक्टूबर) के अनुसार जॉर्डन की विख्यात संगठन 'आरआईएसएससी' ने विश्व के प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं की सूची प्रकाशित की है, जिसमें जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी को निरंतर तेरहवी बार विश्व के 50 सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में शामिल किया है। इससे पूर्व इस सूची में बरेलवी संप्रदाय के प्रमुख अख्तर रजा खान भी शामिल थे। मगर उनका निधन हो चुका है। इस संगठन ने महमूद मदनी की मिल्ली और सामाजिक सेवाओं पर भी विस्तृत प्रकाश डाला है।

केला खाने पर सीरिया के शरणार्थी तुर्की से निष्कासित

अवधनामा (2 नवंबर) के अनुसार तुर्की में शरण लेने वाले सीरिया के कई शरणार्थियों को केला खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होने के बाद उन्हें तुर्की से निकाल दिया गया है। अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की सरकार के मुताबिक इस वीडियो के वायरल होने से शरणार्थियों और स्थानीय नागरिकों के बीच तनाव पैदा हुआ है। इस वीडियो में सात शरणार्थियों को केला खाते हुए दिखाया गया था और उनकी स्थानीय लोगों से झड़प हुई थी। एक तुर्की महिला ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक ओर तो आप शरणार्थी होने का दावा करते हैं और दूसरी ओर केले खाते हैं। इस पर एक शरणार्थी ने उत्तर देते हुए कहा था कि आपलोग

अपने घरों में आराम से रह रहे हैं और दर्जनों केले खरीद रहे हैं। क्या मैं एक केला खरीदकर नहीं खा सकता? इस वीडियो के वायरल होने पर तुर्की सरकार ने इन सातों शरणार्थियों को हिरासत मे लेने के बाद तुर्की से निष्कासित कर दिया है।

मौलाना हकीम अब्दुल्ला को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड

मुंबई उर्दू न्यूज (31 अक्टूबर) के अनुसार मिल्ली काउंसिल के अध्यक्ष और अन्य अनेक इस्लामिक संगठनों से संबंधित मालाना हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला मुगेसी को इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज ने नौवां आईओएस अवार्ड देने की घोषणा की है। अब तक आठ लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। पहला अवार्ड 2007 में देश के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश ए. एम. अहमदी को दिया गया था। दसरा अवार्ड इमारत-ए-शरिया के पमुख मौलाना वली रहमानी, तीसरा अवार्ड पूर्व राज्यपाल ए.आर. किदवई, चौथा अवार्ड प्रो. बी. शेख अली, पांचवां अवार्ड मौलाना डॉ. सईद अल आजमी नदवी, छठा अवार्ड ए.जे. नुरानी, सातवां अवार्ड प्रो. अख्तरूल वासे और आठवां अवार्ड प्रो. मोहसिन उस्मानी नदवी को दिया जा चुका है। इस अवार्ड के तहत एक मोमेंटो और एक लाख का चेक पेश किया जाता है। मौलाना हकीम अब्दुल्ला की उम्र 84 वर्ष की है और उन्होंने दारूल उलूम देवबंद से शिक्षा प्राप्त की थी।

मौलाना अरशद मदनी विवादों के घेरे में

मुंबई उर्दू न्यूज (20 अक्टूबर) के अनुसार मुसलमानों के अमीर-उल-हिंद मौलाना अरशद मदनी हिंदूवादी टेलिविजन 'सूदर्शन न्यूज' पर इंटरव्यू देकर विवाद में फंस गए हैं। समाचारपत्र ने लिखा है कि अरशद मदनी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नजदीकी तेजी से बढ़ रहो है और इसके कारण मुसलमानों में जबर्दस्त भ्रांति पैदा हो रही है। इस प्रमुख मुस्लिम नेता ने कुछ दिन पूर्व संघ के मुख्यालय झंडेवालान में जाकर सरसंघचालक मोहन भागवत से गुप्त मुलाकात की थी और अब उन्हांने मुस्लिम विरोध के कारण बदनाम हिंदूवादी चैनल 'सुदर्शन न्यूज' को इंटरव्यू दिया है। इसके कारण देश के मुसलमानों में भारी बेचैनी है। सामाजिक कार्यकर्ता सुराब ककवानी ने आरोप लगाया है कि मौलाना अरशद मदनो मुस्लिम विरोधियों के हाथों में खेल रहे हैं और इससे अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन हो रहो है। उलेमा काउंसिल के महामंत्री मौलाना अहमद खान दरियाबादी ने यह संदेह व्यक्त किया है कि अब यह मुस्लिम विरोधी टीवी चैनल मौलाना के इंटरव्यू को तोड़-मरोड़कर पेश करगा जिससे मुसलमान बदनाम होंगे।

मुंबई उर्दू न्यूज के संपादक शकील रशीद का कहना है कि मौलाना स्वयं जाहिलों के चंगुल में फंस गए हैं और उन्होंने सारी मुस्लिम उम्मत की इज्जत को दांव पर लगा दिया है। सच यह है कि आजकल इनकी भगवा परिवार से खूब बन रही है। मौलाना अतहर दहलवी का कहना है कि मदनी साहब को इस जाहिल और खुले मुस्लिम दुश्मन से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। मिल्लत टाइम्स के मुख्य संपादक शम्स तबरेज ने कहा है कि मौलाना संघी चैनलों और उनके नेताओं के मकड़जाल में उलझ गए हैं। मौलाना यासिर नदीम अल वजीदी ने कहा है कि मौलाना की इस्लाम दुश्मन हरकतों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

RNI No. DELHIN/2017/72722

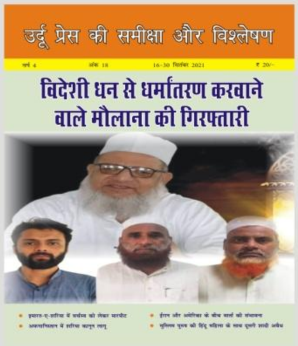

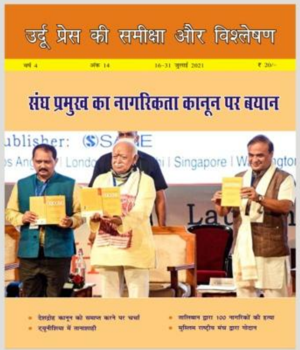

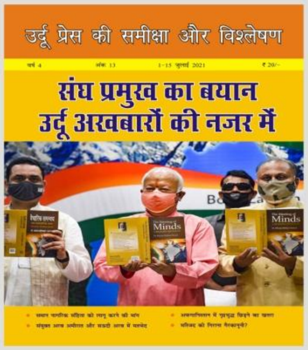

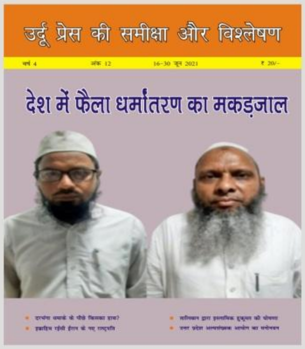

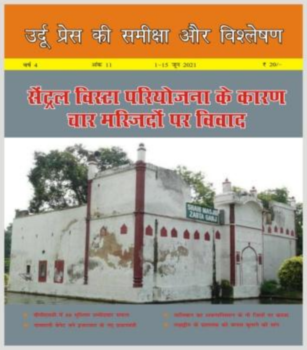

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम ॥

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in